75

to the new lending discipline. Such borrowers may also be granted additional limits, where necessary, to meet increased production need but it shall be ensured that the existing WCTL component is not enhanced and they bring in additional proportionate contribution for the purpose of increased production.

(ii) It is not the intention to have separate limits for peak level and non-peak level in all cases. Such limits are to be fixed only wherever feasible i.e. where there are pronounced seasonal variation in the utilisation of limits. As regards ad-hoc/temporary limits in excess of the sanctioned limits, the intention is not to deny genuine additional credit requirements of borrowers, In genuine cases, it should not be difficult for the borrowers to convince their bankers regarding such ad-hoc limits.

(iii) It is not correct to generalise that industry has been subjected to financial rigours as a result of implementation of Tandon Committee Recommendations. The Tandon Committee has brought about discipline and improvement in the use of working capital by making bank credit need based. The various norms etc. prescribed by it have been kept under constant review by Reserve Bank and banks have been given discretion to allow, if satisfied, deviations from the norms,

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में चलाये जा रहे उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी

1643. श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में चलाये जा रहे उद्योगों में कार्य कर रहे स्थायी ग्रीर ग्रस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रो सवाई सिंह सिसोदिया): सम्भवतः माननीय सदस्य का श्राशय विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनकी स्थार्याः श्रीर श्रस्थार्याः श्रीणयो के ब्यौरे से है । केन्द्रीय सरकारी पद्धति की भांति सभी सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों का श्रावश्यक रूप से स्थार्याया सस्थार्याः श्रीणयों में वर्गीकरण नहीं किया जाता है । कुल कर्मचारियों का स्थार्यः एवं श्रीणयों में विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों

में कुल कर्मचारियों का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

## विवरण

ग्रान्ध्र प्रदेश	66,256
श्रसम	28,821
बिहार	4,19,486
गुजरात	39,987
हरियाणा	8,702
हिमाचल प्रदेश	10,380
जम्मू एवं कश्मीर	1,414
कर्नाटक	1,13,217
केरल	25,886
मध्य प्रदेश	2,35,369
महाराष्ट्र	1,48,375
उड़ीसा	61,232
पंजाब	8,085
राजस्थान	30,132
तमिल नाडु	64,019
उत्तर प्रदेश	67,449
पश्चिम बंगाल	3,61,421

ग्रन्य राज्य एवं केन्द्र	
शासित प्रदेश	11,1 87
दिल्ली	70,400
गोग्रा	1,664
स्रवर्गीकृत	1,00,247

. \_\_\_\_

18,73,729

## Settlement of Demands of Public Sector Employees

1644. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Prime Minister has received a Joint Memorandum from the Central Committee Members of six major trade unions;
- (b) if so, the points raised in the memorandum; and